

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2, 3 और 4 जून 2021 को बैठक की और उभरती समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। अपने आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मत दिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

एमपीसी की अप्रैल की बैठक के बाद से, कोविड-19 की दूसरी लहर कई राज्यों में बढ़ी है और छोटे शहरों और गांवों में फैल गई है, इसके कारण मानवीय दुख और त्रासदी बढ़ी है। फिर भी परीक्षणों और कष्टों के इन दिनों में, वायरस को हराने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। विजयी होने के लिए कठिन समय कठिन विकल्पों और कठिन निर्णयों का आह्वान करता है। ऐसा कहा जाता है कि तूफान से पेड़ों की जड़ें और गहरी होती हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे हम वायरस को खत्म करने के लिए अपनी सहनशक्ति बढ़ाएंगे, यह मानव चरित्र और क्षमता के बेहतरीन पहलुओं को सामने लाएगा। मुझे यहां ग्रीक दार्शनिक एपिकटेटस का एक उद्धरण याद आ रहा है: "जितनी बड़ी कठिनाई होगी, उतना ही अधिक आनंद उसे पार करने में होगा..."¹

मैं एमपीसी के निर्णय के अंतर्निहित तर्क के निर्धारण से शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई 2021 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 के लिए भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संकुचन को 7.3 प्रतिशत रहा, और जीडीपी की वृद्धि

चौथी तिमाही में 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी। सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान, कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था का लचीलापन, व्यवसायों द्वारा कोविड संगत परिचालन मॉडल को अपनाना, और वैश्विक सुधार की गति ऐसी ताकतें हैं जो दूसरी लहर थमने के बाद घरेलू आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए अनुकूल गति प्रदान कर सकती हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार और शहरी मांग की कमी ने नकारात्मक जोखिम पैदा किया है। टीकाकरण अभियान को तेज कर और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति में कमी को कम करके इस महामारी के विनाश को कम किया जा सकता है।

अप्रैल के लिए मुद्रास्फीति प्रिंट 4.3 प्रतिशत पर अपने साथ कुछ राहत और नीति विस्तार लेकर आया है। एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ आरामदायक बफर स्टॉक से अनाज की कीमतों के दबाव को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों और रसद लागतों में व्यापक उछाल के भीतर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ते प्रक्षेपवक्र से लागत की स्थिति खराब हो रही है। ये घटनाक्रम कोर मूल्य दबावों को उंचा रख सकते हैं, हालांकि कमजोर मांग की स्थिति उपभोक्ता मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है।

एमपीसी का विचार था कि इस मोड़ पर, संवृद्धि की गति को फिर से हासिल करने के लिए सभी तरफ से नीतिगत समर्थन जो कि 2020-21 की दूसरी छमाही में स्पष्ट थी और इसके जड़ पकड़ने के बाद बहाली को पोषित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति आगे के समय में भी लक्ष्य के भीतर बनी रहे, नीतिगत दर को 4 प्रतिशत के अपने मौजूदा स्तर पर बनाए रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और संवृद्धि को स्थायी आधार पर पुनर्जीवित और बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

कोविड-19 की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में अप्रत्याशित रूप से रुग्णता और मृत्यु दर की उच्च दर से जुड़ी है।

* गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021

¹ एपिकटेटस: उद्धरण और तथ्य, ब्लागो किरोव (2016)

म्यूटेंट स्ट्रैन का फैलाव जिससे वायरस ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमित किया और उसके कारण देश के एक बड़े हिस्से में गतिविधि पर नए प्रतिबंध लगाए गए। फिर भी पहली लहर के विपरीत, जब अर्थव्यवस्था एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत अचानक रुक गयी थी, गतिशीलता पर क्षेत्रीय आधार पर और सूक्ष्म अंतर से प्रतिबंध होने के कारण, दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा, लोग और व्यवसाय महामारी की कामकाजी परिस्थितियों के अनुकूल हो रहे हैं।

शहरी मांग, जो कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है - बिजली की खपत; रेलवे माल ट्राफिक; बंदरगाह कार्गो; स्टील की खपत; सीमेंट उत्पादन; ई-वे बिल; और टोल संग्रह - में अप्रैल-मई 2021 के दौरान क्रमिक नरमी दर्ज की गई क्योंकि अधिकांश राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों / लॉकडाउन के कारण विनिर्माण और सेवा गतिविधि कमजोर हुई थी। अप्रैल-मई के दौरान गतिशीलता संकेतकों में गिरावट आई है, लेकिन वे पिछले वर्ष की पहली लहर के दौरान देखे गए स्तरों से ऊपर बने हुए हैं। घरेलू मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक अनुकूल और सहायक बनी हुई हैं। इसके अलावा, आने वाले महीनों में टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और इससे आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने में मदद मिलेगी।

बाहरी मांग में मजबूती के साथ, वैश्विक व्यापार में एक पलटाव हो रहा है, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्र को समर्थन मिलना चाहिए। राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टीकाकरण की तेज प्रगति से वैश्विक मांग की स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है। भारत के निर्यात में मार्च, अप्रैल और मई 2021 में तेजी आई है। पूर्व-महामारी के स्तर से परे एक स्थायी बहाली के लिए अनुकूल बाहरी परिस्थितियां बन रही हैं। इस समय निर्यात के लिए संवर्धित और लक्षित नीतिगत समर्थन की मांग है। अब गुणवत्ता और मापनीयता पर ध्यान केंद्रित करके नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त है।

अप्रैल में ग्रामीण मांग के संकेतकों की क्रमिक गिरावट के बावजूद, ग्रामीण मांग के मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के अनुसार आगे चलकर मानसून

के अपनी आधिक्य को बनाए रखने का अनुमान है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमणों का बढ़ता प्रसार नकारात्मक जोखिम पैदा करता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब 2021-22 में 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें 2021-22 की पहली तिमाही में 18.5 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 6.6 प्रतिशत शामिल है।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण की बात करें तो अप्रैल में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 1.2 प्रतिशत अंक की कमी लाने वाले अनुकूल आधार प्रभाव, वर्ष की पहली छमाही तक जारी रह सकते हैं, जो मानसून की प्रगति और सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों के कारण प्रभावित हो सकता है। मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक जोखिम दूसरी लहर के बने रहने और वस्तुतः अखिल भारतीय आधार पर गतिविधि पर परिणामी प्रतिबंधों से उत्पन्न होता है। ऐसे परिदृश्य में, आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों से आवश्यक खाद्य पदार्थों की रोधक कीमतों के लिए केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा समन्वित, कैलिब्रेटेड और समय पर उपायों के लिए सक्रिय निगरानी और तैयारी की आवश्यकता होगी, ताकि आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और खुदरा मार्जिन में वृद्धि को रोका जा सके।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान 5.1 प्रतिशत: 2021-22 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं।

चलनिधि और वित्तीय बाजार मार्गदर्शन

इस महामारी के दौरान रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अनुकूल वित्तीय स्थितियाँ बनाना रहा है ताकि वित्तीय बाजार और संस्थान सामान्य रूप से कार्य करते रहें। तदनुसार, पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि सुनिश्चित की गई है और दबावग्रस्त संस्थानों और क्षेत्रों को लक्षित चलनिधि प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप, उधार लेने की लागत और स्प्रेड ऐतिहासिक निम्न स्तर तक कम हो गए हैं। इससे वित्त वर्ष 2020-21 में

कॉर्पोरेट बॉण्ड और डिबेंचर के माध्यम से निजी उधारी की रिकॉर्ड राशि को प्रोत्साहन मिला है। 28 मई 2021 को आरक्षित मुद्रा में 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)² की वृद्धि हुई, जबकि मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 9.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (21 मई को) और बैंक ऋण में 6.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (21 मई को) की वृद्धि हुई। जी-एसएपी परिचालन और जी-सेक नीलामियों के रद्दीकरण, हस्तांतरण और ग्रीनशू विकल्पों के प्रयोग के कुछ उदाहरणों ने रिजर्व बैंक के विचारों को बाजार तक पहुंचा दिया है। इस वित्तीय वर्ष में दूसरी लहर तेज होने के साथ, रिजर्व बैंक का ध्यान तेजी से प्रणालीगत चलनिधि से अपने समान वितरण की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में, भारतीय संदर्भ में महामारी के अनुभव से स्थायी सबक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों का नियोजन है जो सभी हितधारकों के बीच चलनिधि वितरित करते हैं। हम महामारी के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को उच्च और टिकाऊ विकास के पथ पर वापस लाने का प्रयास करते हुए हम संचरण के बाजार-आधारित चैनलों पर भरोसा करते हुए अपने सक्रिय और प्रथम दृष्टिकोण के साथ अग्रसर रहेंगे।

जी-एसएपी 1.0 के तहत नीलामियों ने अब तक की गई दो नीलामियों में क्रमशः 4.1 और 3.5 के बोली कवर अनुपात के साथ, बाजार सहभागियों से गहरी दिलचस्पी पैदा की है। दूसरी नीलामी का समय 22 मई 2021 से प्रभावी, निवल मांग और मियादी देयता (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत के अपने पूर्व-महामारी स्तर पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बहाली के कारण चलनिधि की निकासी को फिर से भरने के उद्देश्य से था। इसके अलावा, मई के अंतिम सप्ताह के दौरान लगभग ₹52,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन ने सीआरआर बहाली को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। जी-एसएपी 1.0 परिचालन से जुड़ी सकारात्मक बाह्यताएँ, अन्य वित्तीय बाजार खंडों, विशेष रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में परिलक्षित होती हैं। वाणिज्यिक पत्र (सीपी), 91-दिवसीय खजाना बिल, और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर ब्याज दरें भी कम और सीमाबद्ध रहीं।

7 अप्रैल 2021 के मेरे वक्तव्य में, मैंने संकेत दिया था कि जी-एसएपी के अलावा, रिजर्व बैंक विशेष ओएमओ सहित

एलएएफ, दीर्घावधि रेपो/प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों, विदेशी मुद्रा परिचालन और खुले बाजार परिचालन के तहत नियमित परिचालन को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चलनिधि की स्थिति मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित होती है और वित्तीय स्थिति सभी हितधारकों के लिए सहायक बनी रहती है। चालू वर्ष के दौरान अब तक, रिजर्व बैंक ने अब तक नियमित ओएमओ किए हैं और जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹60,000 करोड़ के अलावा ₹36,545 करोड़ (31 मई तक) की अतिरिक्त चलनिधि डाली है। प्रतिफल वक्र के सुचारु विकास की सुविधा के लिए 6 मई 2021 को ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत एक खरीद और बिक्री नीलामी भी आयोजित की गई है। आगे चलकर, रिजर्व बैंक चलनिधि प्रबंधन के लिए नियमित परिचालन करना जारी रखेगा।

इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹40,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए जी-एसएपी 1.0 के तहत एक और परिचालन 17 जून 2021 को आयोजित किया जाएगा। इसमें से, ₹10,000 करोड़ में राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की खरीद शामिल होंगे। बाजार को समर्थन देने के लिए 2021-22 की दूसरी तिमाही में जी-एसएपी 2.0 आरंभ करने और ₹1.20 लाख करोड़ का द्वितीयक बाजार खरीद परिचालन करने का भी निर्णय लिया गया है। जी-एसएपी 2.0 संचालन के तहत विशिष्ट तिथियों और प्रतिभूतियों को अलग से दर्शाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाजार जी-एसएपी 2.0 की इस घोषणा पर उचित प्रतिक्रिया देगा।

अप्रैल-मई में छंटनी की जोखिम-मुक्त अवधि के बाद, भारत में पूंजी प्रवाह की संभावनाएं फिर से सुधर रही हैं। हालांकि ये प्रवाह बाहरी वित्तपोषण बाधाओं को कम करते हैं, चलनिधि में अवांछनीय और अनपेक्षित उतार-चढ़ाव पैदा करते हुए वे वित्तीय बाजारों और परिसंपत्ति की कीमतों में अस्थिरता भी प्रदान करते हैं, जो मौद्रिक नीति के रुख को बिगाड़ सकते हैं। इसने वित्तीय बाजार और चलनिधि स्थितियों को स्थिर करने के लिए हाजिर, वायदा और वायदा बाजारों में रिजर्व बैंक द्वारा दो तरफा हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ताकि मौद्रिक नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने घरेलू अभिविन्यास और स्वतंत्रता बनाए रखे। इस प्रकार, रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से

² आरक्षित नकदी निधि अनुपात में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित।

विदेशी मुद्रा बाजार और इसके विभिन्न खंडों में खरीद और बिक्री दोनों में शामिल है। इन प्रयासों की सफलता बाजार की स्थितियों में स्थिरता और व्यवस्था और बड़े वैश्विक स्पिलओवर के बावजूद विनिमय दर में परिलक्षित होती है। इस प्रक्रिया में, आरक्षित मुद्रा के संचय से देश के तुलन-पत्र को मजबूती मिलती है।

एक और मुद्दा जिसने अर्थशास्त्रियों, बाजार सहभागियों और विश्लेषकों के बीच व्यापक रुचि और चर्चा उत्पन्न की है, वह है हमारे आगामी मार्गदर्शन की भूमिका और प्रकृति। जैसा कि आपको विदित होगा, अप्रैल में एमपीसी ने समय-आधारित आगामी मार्गदर्शन के बजाय स्थिति-आधारित का निर्णय लिया था, यह मानते हुए कि महामारी के संदर्भ में यह पूर्णतः अनुमान लगाना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है और कब आर्थिक सुधार मजबूती से जुड़ जाता है। इस तरह की व्यापक अनिश्चितता के बीच, रिज़र्व बैंक अपने नियंत्रण में सभी लिखतों का उपयोग करना जारी रखेगा और टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए काम करेगा। यह बताने की जरूरत नहीं है, हमारे संचार की निरंतरता और विश्वसनीयता हमारे दृश्यमान कार्यों द्वारा प्रबलित होती है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि महामारी से लड़ने की पूरी प्रक्रिया में, वित्तीय प्रणाली की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थाओं में ठोस कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ पर्याप्त प्रावधानीकरण और पूंजी बफर का निर्माण, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के हमारे प्रयासों में सबसे आगे हैं। रिज़र्व बैंक एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जिसमें वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए एक मजबूत और कुशल वित्तीय क्षेत्र फलता-फूलता है।

अतिरिक्त उपाय

इस पृष्ठभूमि में और समष्टि आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (भाग-बी) में उल्लिखित किया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं।

संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए मांग पर चलनिधि विंडो

कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों पर महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ 31 मार्च 2022 तक ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो खोली जा रही है। इस योजना के तहत बैंक, होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक कार्य/ विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून शामिल हैं, को नए ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रोत्साहन के माध्यम से, बैंकों को अपनी अधिशेष चलनिधि को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक रिज़र्व बैंक के पास प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत उस दर पर रखने की अनुमति दी जाएगी जो रेपो दर से 25 बीपीएस कम है या, एक अलग तरीके से कहा जाए तो, जो प्रतिवर्ती रेपो दर से 40 बीपीएस अधिक है।

सिडबी को विशेष चलनिधि सुविधा

विकास आवेगों जो अभी नए हैं, को पोषित करने और वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2021-22 में नए ऋण देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को 7 अप्रैल 2021 को ₹50,000 करोड़ की नई सहायता दी थी। इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ₹15,000 करोड़ शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विशेष रूप से छोटे एमएसएमई और ऋण की कमी वाले और आकांक्षी जिलों सहित अन्य व्यवसायों की वित्त पोषण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नए मॉडल और संरचनाओं के माध्यम से उधार/ पुनर्वित्त के लिए सिडबी को ₹16,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा प्रचलित नीतिगत रेपो दर पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी, जिसे इसके उपयोग के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत एक्सपोजर थ्रेसहोल्ड का संवर्धन

रिजर्व बैंक द्वारा 5 मई 2021 को घोषित रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में एमएसएमई के साथ-साथ गैर-एमएसएमई छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह को सक्षम करने की दृष्टि से, एमएसएमई, गैर-एमएसएमई छोटे व्यवसाय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण के लिए अधिकतम कुल एक्सपोजर थ्रेसहोल्ड ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ करके योजना के तहत उधारकर्ताओं के कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

एफपीआई की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए मार्जिन का निर्धारण

रिजर्व बैंक भारतीय ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय कर रहा है। एफपीआई द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन बाधाओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अधिकृत डीलर बैंकों को अपने एफपीआई ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों (राज्य विकास ऋण और खजाना बिल सहित) में उनके लेनदेन के लिए, बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर मार्जिन रखने की अनुमति दी जाए।

जमा प्रमाणपत्र जारी करने वालों द्वारा चलनिधि प्रबंधन में लचीलेपन को सुगम बनाना

दिसंबर 2020 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रतिस्पर्धी दरों पर आरआरबी द्वारा अधिक कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक की तरलता विंडो के साथ-साथ कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी। आरआरबी द्वारा अल्पावधि निधि जुटाने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि आरआरबी को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने की अनुमति दी जाए। यह

भी निर्णय लिया गया है कि सीडी के सभी जारीकर्ताओं को कुछ शर्तों के अधीन परिपक्वता से पहले अपनी सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इससे चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलेपन की सुविधा होगी।

सप्ताह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता

एनएसीएच, एनपीसीआई द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली, एक-से-कई क्रेडिट ट्रांसफर जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन, आदि के भुगतान के साथ-साथ बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण संबंधी आवधिक किश्तें, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम, आदि से संबंधित भुगतानों की सुविधा प्रदान करती है। एनएसीएच बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का एक लोकप्रिय और प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। इससे वर्तमान कोविड-19 के दौरान समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी प्रदान करने में मदद मिली है। ग्राहक सुविधा को और बढ़ाने के लिए, और आरटीजीएस की 24x7 उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, एनएसीएच जो वर्तमान में बैंक के कार्य दिवसों पर उपलब्ध है, को 1 अगस्त 2021 से प्रभावी सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

इन सभी उपायों के लिए संबंधित निर्देश/परिपत्र अलग से जारी किए जाएंगे।

समापन टिप्पणी

बीते वर्ष में, रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को महामारी के कहर से बचाने में लगा हुआ है। हम निरंतर चौकसी पर रहे हैं - पहली लहर में ; लहरों के बीच की खामोशी; और अब दूसरी लहर। सभी हितधारकों के लिए वित्तीय स्थिरता और अनुकूल वित्तपोषण शर्तों को बनाए रखना एक प्रतिबद्धता है जिसका हमने दृढ़ता से पालन किया है। कोविड -19 संक्रमणों और घातक घटनाओं में अचानक वृद्धि ने नई बहाली को प्रभावित किया है, लेकिन इसे निकाल नहीं सका है। विकास के आवेग अभी भी जीवित हैं। दूसरी लहर के सामने समग्र आपूर्ति की स्थिति ने लचीलापन दिखाया है।

हम लीक से हटकर सोचना और कार्य करना जारी रखेंगे, सबसे बुरे समय के लिए योजना बना रहे हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। आज घोषित किए गए उपायों, और अब तक उठाए गए अन्य कदमों के संयोजन के साथ, विकास प्रक्षेपवक्र को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद है जिससे हम फिसल गए हैं। आगे देखते हुए, फार्मा उत्पादों के उत्पादन में नेतृत्व के साथ विश्व की वैक्सीन राजधानी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक नीतिगत पैकेज कोविड कथा को बदल सकता है।

यह समय वर्तमान स्थिति से अभिभूत होने का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से इससे उबरने की आवश्यकता है। अनिश्चितता और घोर निराशा के बीच दुर्लभ साहस और अदम्य भावना के कई उदाहरण हमारे देश के भविष्य में एक मजबूत विश्वास की जड़ें जमा चुके हैं। हमारे लचीलेपन, दृढ़ विश्वास और आशा को महात्मा गांधी के शब्दों में सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है: "मैंने अपना आशावाद कभी नहीं खोया है। सबसे अँधेरे समय में मेरे भीतर आशा की किरण जल उठी है....."³।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

³ महात्मा गांधी के संकलित कार्य (सीडब्ल्यूएमजी), खंड 66, पृष्ठ 72